



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

Ms. S.
9/3/98
9/3/98

सं० 17]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 1998/पौष 26, 1919

No. 17]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 1998/PAUSA 26, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998

विषय :—जर्मनी, जापान, कोरिया, चीन और चेक गणराज्य से औद्योगिक सिलाई मशीन की सुइयों के आयात से संबंधित पाटन रोधी जाँच की शुरुआत।

सं. 23/1/97-ए डी डी.—मै. अलटेक लामर्ज नीडल्स लिमिटेड ने जर्मनी, जापान, कोरिया गणराज्य, चीन और चेक गणराज्य (जिन्हें इसके बाद उक्त देश भी कहा जाएगा) से औद्योगिक सिलाई मशीन की सुइयों के पाटन का दोषारोपण करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा जाएगा) के समक्ष सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1955 एवं सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, आकलन तथा वसूली एवं क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार एक याचिका दायर की है और प्रतिपाटन जाँच एवं प्रतिपाटन शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

1. घरेलू उद्योग : याचिका मै. अलटेक लामर्ज नीडल्स लि., 86-बी, सान थोम हाई रोड, राजा अन्नामलाईपुरम, चेन्नई-600028 द्वारा दायर की गई है। चूंकि याचिकाकर्ता भारत में औद्योगिक सिलाई मशीन की सुइयों का एक मात्र निर्माता है, इसलिए वह सम्पूर्ण घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है और याचिका दायर करने का हकदार है।

2. विचाराधीन उत्पाद : मौजूदा जाँच में शामिल उत्पाद औद्योगिक सिलाई मशीन की सुइयां हैं। इन सुइयों का उपयोग मुख्यतः वस्त्र और चमड़ा मदों की सिलाई में किया जाता है। विचाराधीन मदें सीमाशुल्क टैरिफ एच एस कोड 8452.30 के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं। फिर भी यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और मौजूदा जाँच के लिए किसी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

3. शामिल देश : मौजूदा जाँच में शामिल देश हैं—जर्मनी, जापान, कोरिया गणराज्य, चीन और चेक गणराज्य।

4. समान वस्तुएं : याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि औद्योगिक सिलाई मशीन की सुई के उत्पादन की प्रक्रिया विचाराधीन पाटित उत्पादों के आकार एवं पद्धति, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के समान है। उन उत्पादों का उपयोग आपस में एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है और एक दूसरे के गुण काफी हद तक मिलते हैं। इसलिए सम्बद्ध कम्पनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को निम्नानुसार जर्मनी, जापान, कोरिया गणराज्य चीन और चेक गणराज्य से आयातित वस्तुओं के समान वस्तु माना जा सकता है।

5. **सामान्य मूल्य** : जर्मनी के संबंध में, याचिकाकर्ता ने एक निर्यातक के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसके पास मूल्यों की दो सूचियाँ हैं। एक स्वदेशी वितरकों के लिए और दूसरी जर्मनी से बाहर के ग्राहकों के लिए। जापान के मामले में याचिकाकर्ता ने निर्यातकों में से एक निर्यातक द्वारा जारी की गई मूल्य सूची की एक प्रति प्रस्तुत की है। कोरिया गणराज्य, चीन तथा चेक गणराज्य के संबंध में याचिकाकर्ता ने मूल्य सूची के अभाव में निकाली गई उत्पादन लागत पर निर्भर किया है।

6. **निर्यात कीमत** : याचिकाकर्ता ने निर्यात कीमत का दावा वाणिज्यिक अधिसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एस) कलकत्ता, से अप्रैल-नवम्बर, 1996 की अवधि के आंकड़ों के आधार पर किया है। चूँकि ये कीमतें सी आई एफ हैं, इसलिए कारखाना द्वार पर कीमत का आंकलन करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने समुद्री भाड़े, बीमा निकासी आदि के लिए समायोजन का दावा किया है।

7. **डम्पिंग मार्जिन** : इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि कथित देशों में विचाराधीन उत्पाद की सामान्य कीमत की तुलना में भारत को किए गए निर्यात की कीमत कम रही है जो यह दर्शाती है कि जर्मनी, जापान, कोरिया गणराज्य, चीन तथा चेक गणराज्य के निर्यातकों द्वारा इसका पाटन किया जा रहा है।

8. **क्षति** : घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक मापक जैसे बाजार हिस्सा, उत्पादन क्षमता, उपयोग तथा घरेलू उद्योग को हुई वित्तीय हानि सामूहिक और समग्र रूप से यह संकेत देते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

9. **पाटनरोधी जाँच आरम्भ करना** : अतः प्राधिकारी कथित देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबंधित सामान के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा उसके प्रभाव के बारे में पाटनरोधी जाँच शुरू करते हैं।

10. **जाँच की अवधि** : वर्तमान जाँच के लिए जाँच अवधि 1 अप्रैल 1996 से 31 मार्च 1997 है।

11. **सूचना का प्रस्तुतिकरण** : कथित देशों के निर्यातकों और भारत के संबंधित ज्ञात आयातकों को निर्धारित प्रपत्र और विधि में संबंधित जानकारी भेजने और निर्दिष्ट प्राधिकारी व अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, एंटी डम्पिंग प्रभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से पत्र भेजे जा रहे हैं। अन्य इच्छुक पार्टी भी जाँच से संबंधित अपना निवेदन नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और विधि में प्रस्तुत कर सकती है।

12. **पब्लिक फाइल का निरीक्षण** : नियम 6(7) के अनुसार कोई भी इच्छुक पार्टी अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत अगोपनीय विवरण वाली पब्लिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है।

13. **समय सीमा** : वर्तमान जाँच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में प्राधिकारी को ऊपर उल्लिखित पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से चालीस दिन के भीतर भेज दी जानी चाहिए। परन्तु ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को जिन्हें अलग से पत्र भेजा जा रहा है, यह सूचना उन्हें अलग से भेजे गए पत्र की तिथि से चालीस दिनों के भीतर भेजनी होगी।

14. उस स्थिति में जहाँ कोई हितवद्ध पार्टी पहुँचने से मना करती है या अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाती है या जाँच में व्यापक रूप से बाधा डालती है या दी गई सूचना किसी भी तरह से अपूर्ण है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं और उपयुक्त समझने पर केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 1998

Subject :—Initiation of anti dumping investigation concerning import of Industrial Sewing Machine Needles originating from Germany, Japan, Korea RP, China and Czech Republic.

No. 23/1/97-ADD.— M/s Altek Lammertz Needles Limited filed a petition, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) alleging dumping of Industrial Sewing Machine Needles from Germany, Japan, Korea RP, China and Czech Republic (hereinafter also referred to as the said countries) and requested for investigations and levy of anti dumping duties.

1. Domestic Industry : Petition has been filed by M/s. Altek Lammertz Needles Ltd., 86-b, San Thome High Road, Raja Annamalaipuram, Chennai 600028. Since the petitioner is the sole manufacturer of Industrial Sewing Machine Needles in India it represents the domestic industry as a whole and has the standing to file the petition.

2. Product Under Consideration : The products involved in the present investigation are Industrial Sewing Machine Needles. These are mainly used for sewing textiles and leather goods. The products under consideration are classified under Customs Tariff H.S. Code 8452.30. The classification is, however, only indicative and in no way binding on the scope of the present investigations.

3. Countries Involved : The countries involved in the present investigation are Germany, Japan, Republic of Korea, China and Czech Republic.

4. Like Goods : The petitioner has claimed that the process of manufacturing Industrial Sewing Machine Needles, the system and sizes of the product under consideration are identical to the product manufactured by the domestic industry. These products are being used interchangeably and have characteristics closely resembling each other. Goods manufactured by the subject company can, therefore, be treated as like articles to the goods imported from Germany, Japan, Korea RP, China and Czech Republic, within the meaning of the Rules.

5. Normal Value : In respect of Germany, the petitioner has furnished evidence with respect to one of the exporters having two sets of price list one for dealers in home country and another for those customers outside the country. In respect of Japan, the petitioner has submitted a copy of price list issued by one of the exporters. In respect of Korea RP, China and Czech Republic the petitioner has relied upon the constructed cost of production in the absence of the price list.

6. Export Price : The petitioner has claimed export price on the basis of data from the Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCIS), Calcutta, for the period (April-November 96). Since these prices are CIF, the petitioners have claimed adjustments for ocean freight, insurance, clearance etc., for working out ex-factory price.

7. Dumping Margin : There is sufficient prima facie evidence that export price to India has been lower than the normal value in the said countries the product under consideration indicating that the same are being dumped by the exporters from Germany, Japan, Korea RP, China and Czech Republic.

8. Injury : Various economic parameters such as market share, production, capacity utilisation and financial losses to the domestic industry collectively and cumulatively indicate that domestic Industry has suffered material injury.

9. Initiation of Anti-Dumping Investigation : The authority, therefore, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the said countries.

10. Period of Investigation : The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April, 1996 to 31st March, 1997.

11. Submission of Information : The exporters in the said countries and importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and make their views known to Smt. Rathi Vinay Jha, Designated Authority and Additional Secretary, Government of India, Ministry of Commerce, Anti Dumping Division, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. Inspection of Public File : In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

13. Time Limit : Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.

14. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, or the information is incomplete in any respect, the Authority may record its findings on the basis of the fact available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

